

(ख) क्या इसको देखते हुए उनको मिलने वाला प्रायःतित अखबारी कागज का कोटा कम कर दिया गया है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं अथवा कोई योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत सभी समाचारपत्रों की प्रकाशन संख्या की जाच की जा सकती है और यदि हां, तो यह जाच-कार्य कब से शुरू हो जायेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) लाइसेंस वर्ष 1976-77 के लिए अखबारी कागज के आवंटन के लिए अब तक प्राप्त आवेदनपत्रों के अनुसार, समाचारपत्रों की प्रसार संख्या में वृद्धि हुई है। 1976-77 के लिए अखबारी कागज संबंधी नीति में भी समाचार-पत्रों के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त कोटे की व्यवस्था है।

(ग) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रिकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार को प्रसार संख्या की जाच करने का अधिकार पत्रों ही प्राप्त है और यह काम नियमित रूप में हो रहा है।

मध्य प्रश्न: मैं कुछ समाचार-पत्रों को बिये गये अखबारी कागज के कोटे की मात्रा

1520. श्री कृष्ण चन्द कछवाय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, झांसी तथा ग्वाल्हेर से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों की प्रसारण संख्या काफी बढ़ा-चढ़ा कर दिखायी गई है जब कि इनकी वास्तविक प्रकाशन संख्या काफी कम है और यदि हां, तो इन समय इनकी प्रकाशन संख्या क्या है; और

(ख) क्या इन समाचार-पत्रों को दिया जाने वाला अखबारी कागज का कोटा बहुत बड़ी मात्रा में काला बाजार में बेचा जाता है और क्या सरकार का विचार ऐसे सभी मामलों की जांच कराने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ग्वालियर और झांसी में जिन 35 समाचारपत्रों की जांच की गई, उनमें से तीन समाचारपत्रों के बारे में प्रसार संख्या आंकी गई संख्या से अधिक पाई गई थी। इन तीनों समाचारपत्रों में से किसी ने भी 1975-76 में अखबारी कागज के कोटे के लिए आवेदन नहीं किया। उज्जैन, भोपाल और ग्वाल्हेर नगरों में समाचारपत्रों की प्रसार संख्या की जाच शीघ्र ही की जानी है।

(ख) काला बाजारी का कोई विशिष्ट आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।

#### Continuance of Satellite Instructional Television Experiment

1521. SHRI RAJDEO SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Indian Space Research Organisation (ISRO) proposes to continue the Satellite Instructional Television Experiment (SITE) even after the expiry of the contract with U.S.A. for the Applications Technology Satellite (ATS) until the country's own national satellite is ready;

(b) if so, whether after the expiry of the contract on the 31st July, 1976 a fresh contract has been signed with U.S.A. for extending the period of the contract till our satellite is ready; and

(c) if not, the proposal of ISRO to continue the experiment?

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF INFORMATION AND